Drive was also undertaken by Public Sector Undertakings, Banks and Insurance Corporations. As against a backlog of 15195, 8960 candidates were offered appointment.

संघ लोक सेवा आयोग के परामर्शों की अवहेलना

1613. **श्री मोहम्मद अफजल उर्फ मीम अफजल** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले पांच वर्षों के दौरान कितने मामलों में संघ लोक सेवा आयोग के परामर्शों की अवहेलना की गई है ; और

(ख) उसके क्या कारण थे ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री श्रीमती मार्गरेट आल्वा (क) पिछले पांच वर्षों के दौरान संघ लोक सेवा आयोग द्वारा की गई सिफारिशों को स्वीकार न किए जाने वाले मामलों की कुल संख्या नीचे दर्शायी गई है :—

वर्ष	ऐसे मामलों की कुल संख्या जिनमें संघ लोक सेवा आयोग ने सिफारिश की	असहमति के मामलों की कुल संख्या
1986–87	17533	30
1987–88	16389	22
1988–89	14705	15
1989–90	14740	10
1990–91	19024	8

(ख) संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिश को स्वीकार न किए जाने के मुख्य कारण ये हैं (i) सेवा रिकार्डों के आधार पर उम्मीदवार की उपयुक्तता के मूल्यांकन में विचारों में मतभेद तथा अन्य संबंधित पहलू (ii) कदाचार के लिए उपयुक्त सजा के संबंध में विचारों में मतभेद।

Problem of Redundent Officers

1614. SHRI S. MADHAVAN: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether Government's attention has been drawn to the news item published in the daily 'Hindu', dated the 23rd May, 1992 under the caption "The problem of redundant Officers" and if so, the number of officers sent back to States; and

(b) whether the State Government have represented that the allotment of I.A.S. Officers to States must be reduced and if so, the steps taken to ease the burden of States?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS (SHRIMATI MARGARET ALVA): (a) The Government is aware of the news item published in the daily 'Hindu' dated 23rd May, 1992 under the caption "The great Delhi Axe and after" which *inter alia* relates to problems of redundant officers. No officer serving at the Centre